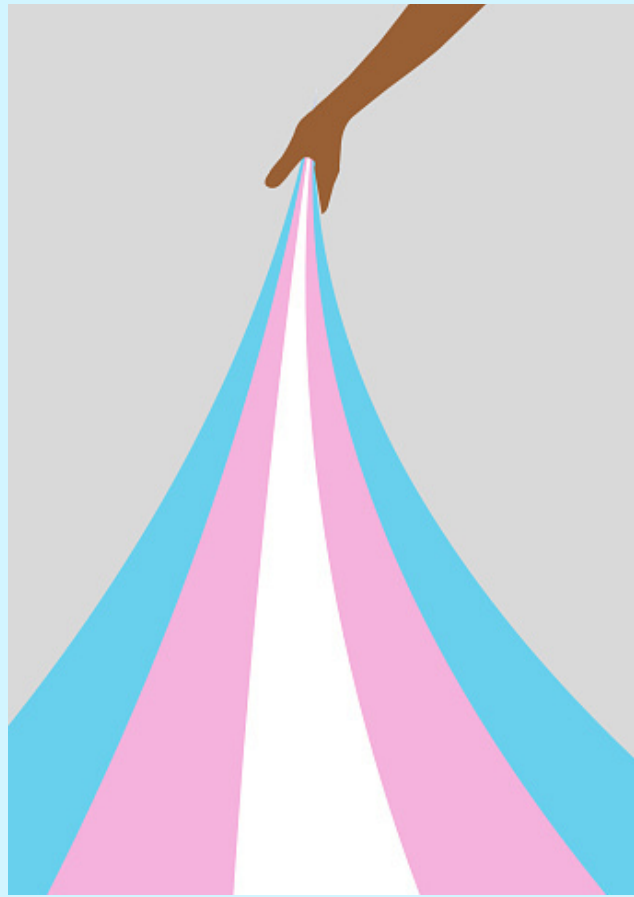


- संवेदीकरण:
- स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकों सहित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा संस्थान और प्रतिष्ठान,
- स्वास्थ्य पेशेवरों का संवेदीकरण;
- कार्यस्थलों में संवेदीकरण कार्यक्रम; तथा
- शिकायत अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम। (नियम 10 (7))
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का प्रावधान (नियम 11 (2))
- जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान (नियम 11 (5))
- शिकायत निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान। (नियम 13)
- हेल्पलाइन और आउटरीच केंद्रों के माध्यम से संचालित एक वर्ष के भीतर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान। (नियम 13 (6))



अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

ट्रांसजेंडर और बेगरी डिवीजन
 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी)
 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
 प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका,
 नई दिल्ली-110075
 टेलीफोन: 011-20893999, 011-20893995
 ईमेल: Directoroffice.nisd@gmail.com
 वेबसाइट: http://www.nisd.gov.in



राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम,
 2019 और नियम 2020

पार्श्वभूमि

ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राचीन इतिहास में मान्यता मिली थी और हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हालाँकि, यह औपनिवेशिक युग में था कि समुदाय के खिलाफ भेदभाव बढ़ गया, जिससे उनके खिलाफ कठोर पूर्वाग्रह पैदा हो गया। बड़े पैमाने पर समाज से उनकी मान्यता और बहिष्कार की कमी के कारण, वे देश के नागरिक के रूप में अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहे हैं। लंबे समय से, उन्हें बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, मानसिक और शारीरिक शोषण, शैक्षिक अवसरों की कमी, संपत्ति के स्वामित्व आदि जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 4,87,803 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं।



"ट्रांसजेंडर व्यक्ति" वह व्यक्ति होता है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति को दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांस-मैन या ट्रांस-वुमन, इंटरसेक्स विविधताओं वाला व्यक्ति, जेंडरक्यूअर और किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगटा जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल हैं।

अधिनियम

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और उनके कल्याण की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10.01.2020 से लागू किया गया था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, भेदभाव के खिलाफ निषेध, सरकार द्वारा कल्याणकारी उपायों, प्रतिष्ठानों और अन्य व्यक्तियों के दायित्व, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद प्रदान करता है। अधिनियम और उसके नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:

भेदभाव के खिलाफ निषेध (धारा 3)

किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ शैक्षणिक प्रतिष्ठानों और उसकी सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता है; रोजगार या पेशा; स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ; आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित किसी भी सामान, आवास, सेवा, सुविधा, लाभ, विशेषाधिकार या अवसर का आनंद या उपयोग; आंदोलन का अधिकार; निवास करने, खरीदने, किराए पर लेने या अन्यथा किसी संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार; और सार्वजनिक या निजी कार्यालय धारण करें;

ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान की मान्यता और स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार (धारा 4)



- जिला मजिस्ट्रेट से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त करने का प्रावधान। लिंग परिवर्तन होने पर संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। (धारा 6 और 7)
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए उपयुक्त सरकारों की बाध्यता। (धारा 8)
- प्रतिष्ठानों के दायित्व। रोजगार में भेदभाव न करना। (धारा 9)
- इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी को नामित करने के लिए स्थापना का प्रावधान। (धारा 11)



- प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निवास का अधिकार प्रदान करता है (धारा 12)
- ऐसे बच्चे के हित में सक्षम न्यायालय के आदेश के अलावा, किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के आधार पर माता-पिता या तत्काल परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। (धारा 12(1))

- व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए प्रावधान (धारा 14)
- स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधान (धारा 15)
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन के प्रावधान (धारा 16 और 17)
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड का प्रावधान जिसमें कारावास भी शामिल है जो छह महीने से कम नहीं होगा और जुर्माने के साथ दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। (धारा 18)



ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम, 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

उपयुक्त सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याणकारी उपायों, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रावधान (नियम 10)